सिविल विविध

न्यायमूर्ति पी. सी. जैन के समक्ष

सियो राम, सरपंच - ***याचिकाकर्ता।***

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - ***उत्तरदाता।***

सिविल याचिका संख्या 1845 सन 1969

14 नवंबर, 1969

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (IV सन 1953) - धारा 17 और 113 - पंजाब ग्राम पंचायत नियम (1965) - नियम 9(1)(b) - क्या पंचायत के अस्थायी मजदूरों पर लागू होता है - सरपंच अपने संबंध को अस्थायी मजदूर के रूप में नियोजित करता है - क्या नियम 9(1)(b) का उल्लंघन करता है - धारा 113- क्या ग्राम सभा की सामान्य बैठकों पर लागू होता है।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17 और पंजाब ग्राम पंचायत नियम, 1965 के नियम 9 के सादे पठन से, एकमात्र निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि नियम 9 (बी) ग्राम पंचायत के कर्मचारियों से संबंधित है, जिन्हें उसमें प्रदान किए गए तरीके से नियोजित किया गया है, न कि उन व्यक्तियों से जो दैनिक आधार पर मजदूरों के रूप में नियोजित हो सकते हैं। धारा 17 ग्राम पंचायत को ऐसे सेवकों को नियोजित करने की शक्ति देती है जो अधिनियम द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं लेकिन रोजगार से पहले, पंचायत समिति का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। यह केवल ऐसे कर्मचारियों पर है जो इस धारा के तहत कार्यरत हैं, नियम 9 के उप-नियम (1) के खंड (बी) में निर्धारित संबंध की पट्टी लागू होती है। इसलिए जहां एक सरपंच अपने संबंध को अस्थायी मजदूर के रूप में नियोजित करता है, वह नियमों के नियम 9 के उप-नियम (1) के खंड (बी) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। (पैरा 9)

यह अभिनिर्णीत किया गया कि अधिनियम की धारा 113 ग्राम सभा की साधारण बैठक पर लागू नहीं होती है। यह केवल सभा की एक बैठक से संबंधित है जिसमें ग्राम पंचायत का बजट और ग्राम पंचायत के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। (पैरा 12)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि सर्टिओरी या किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या-2 के आदेश *दिनांकित 25 जून,* 1969 को रद्द कर दिया जाए।

आई.एस. सैनी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से ।

डी.एस. तेवतिया, एडवोकेट-जनरल, हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए।

चौधरी दलीप सिंह के वकील मलूक सिंह, प्रतिवादी नंबर 4 के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति पी.सी. जैन- सियो राम ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए यह याचिका दायर की है, जिसमें उपायुक्त, गुड़गांव, प्रतिवादी संख्या 2, के 25 जून, 1969 के आदेश (याचिका का अनुबंध 'ए -4')को रद्द करने कि याचना कि गई है।

2) याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता को 1964 में ग्राम पंचायत, बुधेरा के सरपंच के रूप में चुना गया था। प्रतिवादी नंबर 4 ओम प्रकाश, सरपंच के रूप में याचिकाकर्ता के चुनाव से पहले, ग्राम पंचायत, बुधेरा के सरपंच थे, और प्रतिवादी नंबर 5, श्री के.ऍल.पोसवाल के निजी और करीबी दोस्त हैं। उन्होंने (प्रतिवादी नंबर 4) ने फिर से याचिकाकर्ता के खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन सफल नहीं हुए। याचिका में कुछ आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन आरोपों को बताना जरूरी नहीं है।

3) यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ जांच शुरू की गई थी और उसे पंचायतों के सहायक निदेशक द्वारा बुलाया गया था। याचिकाकर्ता ने जांच में भाग लिया और याचिका में किए गए कथन के अनुसार, सहायक निदेशक संतुष्ट थे कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई थी। हालांकि, याचिकाकर्ता को 23 अप्रैल, 1969 को एक कारण बताओ नोटिस मिला, जिसमें उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 102 (2) (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए (प्रति याचिका के अनुलग्नक 'ए -2' के रूप मे संगलन)। याचिकाकर्ता द्वारा एक जवाब भेजा गया था, जिसकी एक प्रति याचिका के अनुलग्नक 'ए -3' है। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसकी वैधता को इस याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।

4) प्रतिवादी संख्या 2, 4 और 5 द्वारा अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए हैं, जिसमें याचिका में लगाए गए भौतिक आरोपों को दूषित किया गया है।

5) पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि यह याचिका स्वीकृत करने के योग्य है। जिन आधारों के आधार पर याचिकाकर्ता को हटाया गया है, उन्हें निम्नानुसार पढ़ा गया है:-

1. ''उन्होंने कहा कि अपने भाई धीग राम को पंचायत के निर्माण कार्यों पर मजदूर के रूप में काम दिलाकर उन्होंने ग्राम पंचायत नियम, 1965 के नियम 9 (बी) का उल्लंघन किया है।

2. जिस भूमि पर पंचायत ने सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कराया है, उससे संबंधित एक मामला न्यायालय में लंबित है। अगर कोर्ट पंचायत के खिलाफ फैसला सुनाता है तो पंचायत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि 3,000 रुपये की लागत से बने कम्युनिटी सेंटर को तोड़ना पड़ेगा। पंचायत का मुखिया होने के नाते उन्होंने निर्माण से पहले जमीन का सही अध्ययन नहीं

किया और इस चूक के लिए वह गंभीर रूप से दोषी हैं।

3. सरपंच बनने के बाद उन्होंने ग्राम सभा की साधारण बैठक नहीं बुलाई और ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 113 का उल्लंघन किया।"

6) कारण बताओ नोटिस, (अनुलग्नक ए-2) में, जिसका जवाब याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया था, याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप निम्नलिखित शब्दों में हैं: –

1. पंचायत के रिकॉर्ड में आपके नाम के खिलाफ 418.48 पैसे की एक मद है और आपने इसे अब तक पंचायत के खातों में जमा नहीं किया है। इस प्रकार आपने इस राशि का दुरुपयोग किया है। इसके अलावा, आपने वर्ष 1965-66 में दुर्गा उत्सव के अवसर पर 323 रुपये की राशि प्राप्त की लेकिन आपने इस राशि को पंचायत निधि में भी जमा नहीं किया है।
2. कि आपने अपने भाई श्री धीग राम को स्कूल और कुएं के कार्यों के निर्माण में मजदूर के रूप में नियोजित किया। उन्होंने इन निर्माण कार्यों पर काम नहीं किया। इसलिए आपने धोखाधड़ी से अपनी मजदूरी से संबंधित इन खर्चों को दिखाया और इसका दुरुपयोग किया।
3. कि स्कूल के निर्माण में, इस्तेमाल की गई ईंटें द्वितीय श्रेणी की थीं जबकि आपने उन्हें प्रथम श्रेणी का दिखाया था।
4. कि आपने पंचायत खातों में हरिजनों के लिए नए कुएं का निर्माण दिखाया है, लेकिन वास्तव में आपने केवल पुराने हरिजन कुएं की मरम्मत की है। इस तरह, आपने झूठा खर्च दिखाने के बाद, उसी का दुरुपयोग किया है।
5. कि आपने सामुदायिक केंद्र के निर्माण पर 3,000 रुपये खर्च किए। जिस भूमि पर इसका निर्माण किया गया है, उससे संबंधित एक मामला गुड़गांव के वरिष्ठ उप-न्यायाधीश की अदालत में लंबित है। इसलिए इतनी जमीन पर भवन का निर्माण करवाकर आपने बेहद आपत्तिजनक काम किया है।

7) कारण बताओ नोटिस में पेश किए गए आरोप 1 और 3 को हटाने का आधार नहीं बनता है। हटाने का पहला आधार यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत नियम, 1965 के नियम 9(b) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जिसमें पंचायत के निर्माण कार्य पर अपने भाई धीग राम को मजदूर के रूप में नियोजित किया गया है। कारण बताओ नोटिस से यह पता चलता है कि आरोप यह था कि धीग राम को स्कूल और कुएं के निर्माण के लिए मजदूर के रूप में नियोजित किया गया था, कि उन्होंने उन निर्माण कार्यों पर काम नहीं किया था और उनकी मजदूरी से संबंधित खर्चों को धोखाधड़ी से दिखाया गया था और दुरुपयोग किया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि कारण बताओ नोटिस में आरोप पूरी तरह से अलग था, जबकि अब जिस आधार को हटाने का आधार बनाया गया है, वह पूरी तरह से अलग है। इस छोटे से आधार पर आक्षेपित आदेश में पहला आधार नजरअंदाज किया जा सकता है। हालांकि, गुण-दोष के आधार पर भी, इस आधार में कोई दम नहीं है। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि धीग राम जो याचिकाकर्ता का भाई है, पंचायत के निर्माण कार्यों पर एक मजदूर के रूप में कार्यरत था। सवाल यह है कि क्या धीग राम को नियुक्त करके, याचिकाकर्ता ने नियमों के नियम 9 (बी) का उल्लंघन किया है। विवाद की सराहना करने के लिए, इस स्तर पर नियम 9 को उसकी संपूर्णता में पुन: पेश करना उचित होगा, जो

निम्नलिखित शब्दों में है: -

"9. *अन्य कर्मचारी का रोजगार।*

1. (a) पंचायत समिति के अनुमोदन के अध्यधीन, और

बजट में निधियों की उपलब्धता के संबंध में, एक ग्राम पान-चायत, एक संकल्प द्वारा, उसके द्वारा अपेक्षित कर्मचारियों की एक सूची तैयार कर सकता है और उन्हें भुगतान किए जाने वाले वेतन और भत्तों और उनमें से प्रत्येक को सौंपे जाने वाले कर्तव्यों का भी निर्णय लेगा।

(b) किसी भी व्यक्ति को ग्राम पंचायत द्वारा नियोजित नहीं किया जाएगा यदि वह अपने किसी सदस्य का निकट संबंधी (भाई, पिता, दादा, पत्नी का भाई और पत्नी का पिता, पुत्र, दामाद) है या यदि उसे नैतिक अधमता से संबंधित किसी आपराधिक अपराध का दोषी ठहराया गया है। पंचायत के किसी भी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा में नहीं रखा जाएगा।

2. पंचायत अच्छे और पर्याप्त कारणों से अपने कर्मचारियों पर निम्नलिखित दंड लगा सकती है:-

i. निंदा

ii. पंचायत की लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन के कारण पंचायत को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक वसूली।

iii. सेवा से हटाना या बर्खास्त करना।

बशर्ते कि कोई जुर्माना लगाने से पहले कर्मचारी को उसके खिलाफ विशिष्ट आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने या कोई सबूत पेश करने का उचित अवसर दिया जाएगा।

3. एक कर्मचारी जिसे उप-खंड (2) के तहत दंडित किया गया है, पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी को कर्मचारी को सजा के आदेश की सूचना के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।

4. ग्राम पंचायत के कर्मचारी की सेवाएं हो सकती हैं। उसे एक महीने का नोटिस देकर या उसके बदले में उस अवधि के लिए एक महीने का वेतन या वेतन देकर समाप्त कर दिया जाता है जिसके द्वारा नोटिस एक महीने से कम हो जाता है।

5. ग्राम पंचायत के कर्मचारी उसी अवकाश के हकदार होंगे जिसके वे हकदार होते यदि वे पंचायत समितियों और जिला परिषद सेवा के सदस्य होते।

बशर्ते कि एक ग्राम पंचायत उतनी ही छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम होगी जितनी पंचायत समिति अपने कर्मचारियों को मंजूरी देने में सक्षम है। अधिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए प्रकरण पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा जाएगा।

6. सरकारी सेवक आचरण नियम, 1955, समय-समय पर यथासंशोधित, ग्राम पंचायत के सेवकों पर तब तक लागू होगा जब तक कि वे अधिनियम के प्रावधानों और इन नियमों के साथ असंगत न हों:

परन्तु उपर्युक्त नियमों में 'सरकार' शब्द और 'सरकारी कर्मचारी' शब्द जहां कहीं भी हों, उनके स्थान पर क्रमशः 'ग्राम पंचायत' शब्द और 'ग्राम पंचायत के कर्मचारी' शब्द प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

8) यह नियम पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 के अनुपालन को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, जो निम्नानुसार है: -

"17. *अन्य नौकरों का रोजगार।*

1. ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जा सकते हैं और पंचायत समिति के पूर्व अनुमोदन से, कोई पंचायत ऐसे अन्य सेवकों को नियोजित कर सकेगी जो इस अधिनियम द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं और ऐसे सेवकों को निलंबित, बर्खास्त या अन्यथा दंडित कर सकती है।
2. एक ग्राम पंचायत सभा निधि से ऐसे सेवकों को पारिश्रमिक का भुगतान करेगी।

9) धारा 17 और नियम 9 को पढ़ने से केवल यह संभव निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नियम 9(ख) ग्राम पंचायत के उन कर्मचारियों से संबंधित है जिन्हें उसमें दिए गए तरीके से नियोजित किया गया है, न कि उन व्यक्तियों से जिन्हें दैनिक आधार पर मजदूरों के रूप में नियोजित किया गया हो। धारा 17 एक ग्राम पंचायत को ऐसे अन्य सेवकों को नियोजित करने की शक्ति देती है जो अधिनियम द्वारा लगाए गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं; लेकिन रोजगार से पहले पंचायत समिति का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। नियम 9 के तहत, कर्मचारियों के रोजगार के लिए एक प्रक्रिया प्रदान की जाती है; इसलिए कर्मचारियों पर लगाए जाने वाले दंड भी। इस नियम के तहत, यह भी प्रावधान किया गया है कि एक कर्मचारी कितनी छुट्टी और किस तरीके से हकदार होगा। उपनियम (6) के अधीन यह कहा गया है कि शासकीय सेवक नियम, 1955 ग्राम पंचायत के सेवकों पर तब तक लागू होगा जब तक वे अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों। यह केवल ऐसे कर्मचारियों पर है जो धारा 17 के तहत कार्यरत हैं, नियम 9 के उप-नियम (1) के खंड (बी) में निर्धारित संबंध की पट्टी लागू होती है। माना कि धीग राम को अधिनियम की धारा 17, नियम 9 के तहत प्रदान किए गए तरीके से कभी नियोजित नहीं किया गया था, न ही वह नियम 9 के उप-नियम (4) के लाभ का दावा करने का हकदार था, इस आशय का कि उसकी सेवाओं को समाप्त करने से पहले एक महीने का नोटिस देना आवश्यक था। उन्हें एक अस्थायी मजदूर के रूप में नियोजित किया गया था और उनकी सेवाओं को किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता था। इस प्रकार मेरा विचार है कि नियम 9 के उप-नियम (1) का खंड (बी) उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है जो अस्थायी मजदूरों के रूप में कार्यरत हैं और याचिकाकर्ता ने अपने भाई धीग राम को निर्माण कार्यों पर मजदूर के रूप में नियोजित करके नियम 9 के उप-नियम (1) के खंड (बी) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है।

10) दूसरा आधार जिस पर निष्कासन आदेश पारित किया गया है, वह यह है कि सामुदायिक केंद्र का निर्माण भूमि के एक टुकड़े पर किया गया है जिसके बारे में अदालत में एक मामला लंबित है। इस आधार को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि विशुद्ध रूप से अनुमानों और अनुमानों पर, याचिकाकर्ता को आधार संख्या 2 पर दोषी ठहराया गया है। यह मामला अभी भी सिविल कोर्ट में लंबित है और सक्षम न्यायालय द्वारा अब तक यह निर्णय नहीं लिया गया है कि जिस भूमि पर सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया गया है, वह पंचायत की नहीं है। उपायुक्त को इस मुकदमे के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और यदि वाद में निर्णय पंचायत के खिलाफ गया था, तो उपायुक्त के लिए

याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का कुछ औचित्य हो सकता है। वर्तमान में, आधार काल्पनिक है और याचिकाकर्ता को हटाने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है।

11) कारण संख्या 3 में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने ग्राम सभा की साधारण बैठक नहीं बुलाकर अधिनियम की धारा 113 का उल्लंघन किया है। जैसा कि कारण बताओ नोटिस से स्पष्ट है, यह आधार कारण बताओ नोटिस में शामिल नहीं था और लागू आदेश के पारित होने के समय पहली बार इसे आधार बनाया गया है। याचिकाकर्ता को इस आधार पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का मौका कभी नहीं दिया गया और इस तरह उसे स्पष्टीकरण का अवसर दिए बिना दंडित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, गुण-दोष के आधार पर भी, इस आधार में कोई दम नहीं है। धारा 113 निम्नानुसार है:-

"113. *ग्राम पंचायतों द्वारा बजट और वार्षिक रिपोर्ट।*

प्रत्येक ग्राम पंचायत अगले वर्ष बैसाख के पहले दिन से शुरू होने वाले वर्ष के लिए अपनी आय और व्यय का बजट अनुमान तैयार करेगी और सभा के समक्ष रखेगी और ग्राम पंचायत के कामकाज की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें भविष्य के विकास कार्यक्रम और अगले वर्ष की योजनाएं होंगी:

परन्तु यदि कोई ग्राम पंचायत सवानी की बैठक में अपना बजट या वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो पंचायत ऐसी ग्राम पंचायत का बजट और वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी और उसे इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई गई सभा की असाधारण आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत करेगी और सभा इस प्रकार तैयार किए गए बजट और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करेगी और सभा क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करेगी।

12) इस खंड की सादी व्याख्या से, यह स्पष्ट है कि ग्राम सभा की साधारण बैठक के लिए इसका कोई आवेदन नहीं है। यह केवल सभा की एक बैठक से संबंधित है जिसमें ग्राम पंचायत का बजट और ग्राम पंचायत के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। वास्तव में, यह अधिनियम की धारा 12 है जो ग्राम सभा की सामान्य बैठकों और कोरम की बात करती है। एक तर्क दिया जा सकता था कि धारा 113 का गलत उल्लेख किया गया था, लेकिन उपायुक्त द्वारा दायर रिटर्न से, यह स्पष्ट है कि अभी भी लिया गया रुख यह है कि अधिनियम की धारा 113 लागू होती है। हालांकि, जैसा कि पहले देखा गया था, लागू आदेश में उल्लिखित आधार, अधिनियम की धारा 113 में निर्धारित परीक्षण को पूरा नहीं करता है। इस प्रकार किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हटाने का कोई आधार नहीं बनाया गया है और आक्षेपित आदेश में उल्लिखित आधार अधिनियम की धारा 102 (2) द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, जहां उन आधारों में प्रावधान किया गया है जिन पर हटाने का आदेश पारित किया जा सकता है:

13) विद्वान अधिवक्ता के पहले तर्क पर मैंने जो विचार किया है, उसके संदर्भ मे मैं विद्वान अधिवक्ता के दूसरे विवादक से निपटने का प्रस्ताव नहीं करता जो था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई थी जिसके आधार पर उसे हटाया जा सके।

14) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, मैं इस याचिका को स्वीकृत करता हूं और उपायुक्त के 25 जून, 1969 के आक्षेपित आदेश (याचिका के अनुलग्नक 'ए -4') को रद्द करता हूं, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देता हूं।

के.एस.के.

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

परीक्षित

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

महम, रोहतक,हरियाणा।